ISSN: 2395-7852

International Journal of Advanced Research in Arts, Science, Engineering & Management

Volume 10, Issue 4, July 2023

INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INDIA

Impact Factor: 6.551

+91 9940572462 +91 9940572462 ijarasem@gmail.com www.ijarasem.com

International Journal of Advanced Research in Arts, Science, Engineering & Management (IJARASEM)

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 6.551 |Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 10, Issue 4, July 2023 |

मतदान मे बढ़ती महिलाओं की भागीदारी भीलवाड़ा के संदर्भ में

[1]Mukesh Kumar Dadwal, [2]Dr. Banwari Lal Menawat

[1]Assistant Professor, Political Science, Balaji Mahila PG College, Sawai Madhopur, Rajasthan, India

[2]Professor and Supervisor, Political Science, Govt. College, Gangapur City, Rajasthan, India

सार

भारत में भीलवाड़ा के संदर्भ में महिलाएं अधिक बार और अधिक संख्या में मतदान कर रही हैं। आज, भारत के दो-तिहाई राज्य चुनावों में महिलाओं का मतदान वास्तव में पुरुषों की तुलना में अधिक रहा है। यह एक गहरे पितृसत्तात्मक, रूढ़िवादी समाज में घटनाओं का एक उल्लेखनीय मोड़ है।

जहां तक आंकड़ों की बात है तो भारत में पुरुष हमेशा महिलाओं की तुलना में अधिक संख्या में वोट देने निकले हैं। हाल ही में 2004 में, राष्ट्रीय चुनावों में पुरुषों को महिलाओं की तुलना में 8.4 प्रतिशत अंक का लाभ मिला। लेकिन 2014 तक यह अंतर घटकर मात्र 1.8 प्रतिशत अंक रह गया।

परिचय

यह एक पहेली बनी हुई है। भीलवाड़ा के संदर्भ में कार्यस्थल पर दबाव और खींचतान के कारकों का एक संयोजन होने की संभावना है: अधिक महिलाएं मतदान करना चाहती हैं, और संस्थाएं उन्हें चुनाव में जाने के लिए और अधिक प्रोत्साहित कर रही हैं।[1]

भीलवाड़ाके संदर्भ में महिलाएँ लगातार अधिक साक्षर, अधिक शिक्षित और समृद्ध होती जा रही हैं। यह उन्हें राजनीतिक रूप से अधिक जागरूक बना सकता है। वे अभूतपूर्व संख्या में सामूहिक आयोजन में भी भाग ले रहे हैं, आमतौर पर छोटे स्थानीय समूहों के माध्यम से जिसमें महिलाएं एक-दूसरे को पैसे बचाने और आपातकालीन जरूरतों के लिए अपने संसाधनों को इकट्ठा करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। कुछ सबूत बताते हैं कि जब महिलाएं इन आर्थिक नेटवर्क में भाग लेती हैं, तो उनके राजनीति में शामिल होने की अधिक संभावना होती है। ये समूह किसी राजनीतिक लक्ष्य को हासिल करने के लिए स्थापित नहीं किए गए थे, लेकिन इनके राजनीतिक परिणाम हो सकते हैं।

भीलवाड़ाके संदर्भ में संस्थाएँ महिलाओं के लिए भी मतदान को आसान बनाने का प्रयास कर रही हैं। उदाहरण के लिए, भीलवाड़ाके संदर्भ में चुनाव आयोग मतदाताओं के डर को कम करने के लिए मतदान केंद्रों की सुरक्षा में सुधार करके और चुनाव के दिन महिलाओं के लिए अलग कतारें स्थापित करके अधिक महिलाओं को मतदान करने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रहा है।

दशकों से, भीलवाड़ा के संदर्भ में मतदान एक पुरुष-प्रधान उद्यम रहा है। और क्योंकि बहुत से पुरुष हमेशा वोट देने के लिए निकले हैं, यह शायद आश्चर्य की बात नहीं है कि मुख्यधारा की पार्टियों ने कभी भी महिलाओं को लुभाने लायक महत्वपूर्ण निर्वाचन क्षेत्र के रूप में नहीं देखा है।[2]

यह प्रशंसनीय प्रतीत होता है कि कुछ चिंताएँ जो महिलाओं पर असमान रूप से प्रभाव डालती हैं - जैसे कि सार्वजनिक सुरक्षा या स्वास्थ्य सेवा - अक्सर पीछे ले ली गई हैं , क्योंकि ऐतिहासिक रूप से महिलाएं पुरुषों की तुलना में राजनीतिक रूप से कम सक्रिय रही हैं।

भीलवाड़ाके संदर्भ में पहले से कहीं अधिक महिलाएं मतदान कर रही हैं, लेकिन मतदान समूह के रूप में उनका कुल आकार अभी भी पुरुषों से पीछे है।

ऐसा इसलिए है क्योंकि भले ही महिला मतदाताओं का प्रतिशत अधिक है, फिर भी भारत की सामान्य आबादी में एक महत्वपूर्ण लिंग असंतुलन है।

देश की 2011 की जनगणना के अनुसार , देश में प्रति 1,000 पुरुषों पर लगभग 943 महिलाएं हैं। विश्व बैंक के अनुसार, यह भारत को 194 देशों में से 186वें स्थान पर सबसे नीचे रखता है ।

भीलवाड़ाके संदर्भ में पंजीकृत मतदाताओं के बीच लिंगानुपात और भी बदतर है।

देश की मतदाता सूची में प्रति 1,000 पुरुषों पर केवल 908 महिलाएं हैं।

इसका मतलब यह है कि, प्रगति के बावजूद, भारतीय महिलाओं को चुनावों में दोहरा झटका झेलना पड़ता है: बेटों के लिए एक मजबूत प्राथमिकता से ऊपर और परे (जिसके परिणामस्वरूप अवैध लिंग-चयनात्मक गर्भपात होता है और लड़कों की तुलना

में लड़कियों के लिए कम शैक्षिक अवसर होते हैं), महिलाओं की तुलना में कम संभावनाएं होती हैं। पुरुषों को मतदान के लिए पंजीकृत किया जाना है ।

भीलवाड़ाके संदर्भ में जैसे-जैसे भारतीय महिलाएं राजनीतिक रूप से अधिक संगठित होती जा रही हैं, यह बदलता दिख रहा है कि भीलवाड़ा के संदर्भ में उम्मीदवार कैसे प्रचार करते हैं और कार्यालय में पहुंचने के बाद वे कैसे शासन करते हैं।

उदाहरण के लिए, भीलवाड़ा के संदर्भ में दोबारा चुने जाने पर एक कठोर नया शराब विरोधी कानून लेकर आए। भीलवाड़ाके संदर्भ में यह प्रतिबंध प्रचार अभियान के दौरान महिलाओं से किये गये वादे से प्रेरित है, जिन्होंने उन्हें बताया था कि अनियंत्रित शराबखोरी उनके परिवारों और समुदायों को तबाह कर रही है।

जैसे-जैसे भारत भीलवाड़ा के संदर्भ में आम चुनावों के लिए तैयार हो रहा है, महिलाओं की स्थिति अभियान की बयानबाजी का केंद्र बिंदु बन गई है। भीलवाड़ा के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला-अनुकूल नीतियों को अपने मंच की पहचान बना लिया है।[3]

मोदी नियमित रूप से कहते हैं कि स्वच्छता में सुधार, कल्याण सब्सिडी में सुधार (लड़कियों की शिक्षा और स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन के प्रावधान जैसी चीजों के लिए) और सार्वभौमिक बैंकिंग की गारंटी देने के उनके प्रशासन के प्रयास भारत की महिलाओं के लिए परिवर्तनकारी हैं।

ऐसा इसलिए है क्योंकि भीलवाड़ा के संदर्भ में अपर्याप्त सेवा प्रावधान का बोझ महिलाओं पर पड़ता है। महिलाओं को रोजमर्रा के उपयोग के लिए पानी इकट्ठा करना, या बीमार बच्चों की देखभाल जैसे दैनिक घरेलू कार्य अपने कंधों पर लेने की अधिक संभावना है। मोदी के दावों का मुकाबला करने के लिए विपक्षी दलों ने भी इस फ्रेमिंग को अपनाया है।

विचार-विमर्श

भीलवाड़ाके संदर्भ में महिला उम्मीदवारों की संख्या बढ़ी है, लेकिन अभी भी लंबा रास्ता तय करना है।

1962 में, पहला आम चुनाव जिसके लिए लिंग पर डेटा मौजूद है, केवल 3.7 प्रतिशत उम्मीदवार महिलाएं थीं। यह आंकड़ा 1991 तक लगभग वही रहा। 1990 के दशक में, राजनीतिक दलों पर महिला उम्मीदवारों को चुनने के लिए अधिक दबाव के कारण, कार्यालय के लिए दौड़ने वाली महिलाओं का अनुपात बढ़ना शुरू हो गया।[5]

भीलवाड़ाके संदर्भ में संसदीय दौड़ में केवल 8 प्रतिशत से अधिक उम्मीदवार महिलाएं थीं। यह, एक बार में, एक बड़ा सुधार है और फिर भी पूर्ण रूप से एक छोटा अनुपात है।

भीलवाड़ाके संदर्भ में चुनावों पर एकत्र किए गए आंकड़ों के अनुसार , राज्य स्तर पर चीजें बेहतर नहीं हैं। 2011 और 2015 के बीच, राज्य कार्यालय के लिए केवल 7.3 प्रतिशत उम्मीदवार महिलाएं थीं।

शोध में पाया गया है कि भीलवाड़ा के संदर्भ में महिलाओं के दो प्रकार के निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ने की अधिक संभावना है। सबसे पहले, जिन निर्वाचन क्षेत्रों में महिलाओं की तुलना में पुरुषों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक है, वहां महिला उम्मीदवार अधिक आम हैं । यह चौंकाने वाली बात है, क्योंकि कोई उम्मीद कर सकता है कि महिलाएं वहां दौड़ेंगी जहां आबादी में उनका बेहतर प्रतिनिधित्व है। लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है.

दूसरा, ऐतिहासिक रूप से वंचित समूहों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में भीलवाड़ा के संदर्भ में महिलाओं के चुनाव लड़ने की अधिक संभावना है । भारत के पास सकारात्मक कार्रवाई की दुनिया में कहीं भी पाई जाने वाली सबसे उन्नत प्रणालियों में से एक है। भीलवाड़ा के संदर्भ में राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर लगभग एक-चौथाई विधायी सीटें दो संरक्षित समूहों के लिए आरक्षित हैं: अनुसूचित जातियां, जो हिंदू जाति पदानुक्रम में सबसे नीचे हैं, और अनुसूचित जनजातियां, जो भारत की मूल, स्वदेशी आबादी बनाती हैं।

ये दोनों पैटर्न हैरान करने वाले हैं और शोधकर्ता सटीक कारण का पता लगाने में सक्षम नहीं हैं। भीलवाड़ा के संदर्भ में लिंगानुपात के निष्कर्ष के बारे में एक सिद्धांत यह है कि महिलाएं उस पद के लिए चुनाव लड़ती हैं जहां आबादी में उनका प्रतिनिधित्व कम है क्योंकि चुनावी मैदान में शामिल होना ही उनकी आवाज को सुनने का एकमात्र तरीका है। जिन स्थानों पर पुरुषों और महिलाओं के बीच अधिक संतुलन है, वहां तर्क यह है कि शायद संख्या में ताकत का मतलब है कि महिलाओं को प्रभाव डालने के लिए राजनेता होने की आवश्यकता नहीं है।

भीलवाड़ाके संदर्भ में आरक्षित सीटों और महिलाओं की उम्मीदवारी के बीच संबंध संभवतः राजनीतिक अवसरवादिता से है। राजनीतिक दलों को महिलाओं के पक्ष में आरक्षित सीटों पर पुरुष पदाधिकारियों को किनारे करना आसान लगता है क्योंकि इन वंचित समुदायों के पुरुषों को अन्य पुरुष पदाधिकारियों की तुलना में अधिक त्याग योग्य माना जाता है। उन्हें कहीं न कहीं महिला उम्मीदवारों का अपना कोटा पूरा करना होगा और इन सीटों को सबसे कम मूल्यवान और आसान विकल्प के रूप में देखना होगा। दुर्भाग्य से, जाति व्यवस्था के पदानुक्रम राजनीतिक दलों के भीतर भी पुन: उत्पन्न होते हैं।[7]

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 6.551 |Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 10, Issue 4, July 2023 |

परिणाम

भीलवाड़ाके संदर्भ में जब उन्हें नामांकित किया जाता है, तो भारतीय महिलाएं अपने वजन से ऊपर मुक्का मारती हैं। उदाहरण के लिए, 2014 में 8.1 प्रतिशत संसदीय उम्मीदवार महिलाएं थीं, लेकिन अंतिम विजेताओं में 11.6 प्रतिशत महिलाएं थीं।

भीलवाड़ाके संदर्भ में इसका मतलब यह नहीं है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में बेहतर राजनेता हैं। यह संभव है कि महिलाओं के पार्टी के गढ़ों में चुनाव लड़ने या कम प्रतिस्पर्धी सीटों पर चुनाव लड़ने की अधिक संभावना है।

भीलवाड़ाके संदर्भ में महिला विधायी सदस्यों के लिए कोटा प्रदान करके महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने की योजना पर विचार कर रही है, जैसा कि देश में अन्य अल्पसंख्यकों के लिए है। एक प्रस्तावित महिला आरक्षण विधेयक , जिसे पहले ही भारत की संसद के ऊपरी सदन द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है, लेकिन निचले सदन में लटका हुआ है, महिलाओं के लिए राज्य और राष्ट्रीय विधायी सीटों में से एक तिहाई आरक्षित करेगा। जबकि अधिकांश पार्टियां इस कदम का समर्थन करने का दावा करती हैं, लेकिन इस बात पर बातचीत रुकी हुई है कि क्या महिलाओं के लिए इस कोटा के भीतर विभिन्न जाति समूहों के लिए उप-कोटा होना चाहिए।

भीलवाड़ाके संदर्भ में भारतीय महिलाओं ने इस बारे में बात करना शुरू कर दिया कि कैसे उन्हें कार्यस्थल के अंदर और बाहर मौखिक और शारीरिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है।[8]

इन आरोपों ने फिल्म, मीडिया, व्यवसाय और यहां तक कि राजनीति की दुनिया को भी प्रभावित किया है। उदाहरण के लिए, पूर्व विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर पर इक्कीस से अधिक महिलाओं ने गलत काम करने का आरोप लगाया था और इन आरोपों के कारण उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा था। हालाँकि अकबर अभी भी अपनी संसदीय सीट बरकरार रखे हुए हैं और उन्होंने आरोपों से लड़ने की कसम खाई है, मंत्री पद से उनका इस्तीफा आंदोलन के लिए एक बड़ी जीत थी। आने वाले हफ्तों और महीनों में राजनेताओं की कोठरियों से कई और कंकाल निकल सकते हैं।

भीलवाड़ाके संदर्भ में इस बात के कुछ प्रमाण हैं कि कार्यालय में अधिक महिलाओं के होने से लैंगिक धारणाएँ बदल जाती हैं।

उदाहरण के लिए, भीलवाड़ा के संदर्भ में स्थानीय राजनीति में महिलाओं के लिए सकारात्मक कार्रवाई के एक अध्ययन में पाया गया है कि, महिला राजनेताओं के होने का मतलब यह नहीं है कि मतदाताओं को पुरुष नेताओं को पसंद करने की संभावना कम है, यह सार्वजनिक और निजी जीवन में लैंगिक भूमिकाओं के बारे में रूढ़िवादिता को कम करने में मदद करता है ।

एक अन्य अध्ययन में पाया गया है कि भीलवाड़ा के संदर्भ में महिला राजनेताओं का होना उनके अधिकार क्षेत्र में रहने वाली लड़कियों की आकांक्षाओं और शैक्षिक उपलब्धि के लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है। अन्य नए शोध में पाया गया है कि महिला प्रतिनिधि उच्च विकास के साथ-साथ कम भ्रष्टाचार और राजनीतिक अवसरवादिता से जुड़ी हैं।[11]

भीलवाड़ाके संदर्भ में यह सुझाव देने के लिए बहुत कम सबूत हैं कि भारत में महिलाएं महिला उम्मीदवारों को वोट देने की अधिक संभावना रखती हैं। प्रमुख महिलाओं के नेतृत्व वाली पार्टियाँ भी महिला मतदाताओं के बीच अन्य पार्टियों से बेहतर प्रदर्शन नहीं करतीं , हालाँकि इसमें बदलाव हो सकता है।

एक अध्ययन में पाया गया है कि मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करने से अधिक महिलाएं मतदान के लिए आती हैं - लेकिन इसके परिणामस्वरूप महिला उम्मीदवारों का वोट प्रतिशत वास्तव में कम हो जाता है। भीलवाड़ा के संदर्भ में एक संभावित व्याख्या यह है कि कई भारतीय महिलाएं, पुरुषों की तरह, अक्सर महिला नेतृत्व के प्रति पूर्वाग्रह रखती हैं।[9]

यह भारत के राजनीतिक और आर्थिक भविष्य का एक केंद्रीय विरोधाभास है। अभूतपूर्व सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण का आनंद लेने के बावजूद, भारतीय महिलाएं तेजी से श्रम बल से बाहर हो रही हैं।

किसी देश की प्रति व्यक्ति आय और श्रम बल में महिला भागीदारी के बीच एक प्रसिद्ध यू-आकार का सांख्यिकीय संबंध है। बहुत गरीब और बहुत अमीर देशों में, महिलाएँ उच्च दर पर कार्यबल में भाग लेती हैं।

लेकिन भीलवाड़ा के संदर्भ में आय वितरण के बीच में, महिलाओं की भागीदारी कम हो जाती है, क्योंकि घर प्रति व्यक्ति आय की एक निश्चित सीमा तक पहुंच जाते हैं जो महिलाओं को घर पर रहने के लिए प्रोत्साहित (या मजबूर) करता है।[10]

निष्कर्ष

समान आय स्तर वाले देशों की तुलना में, भीलवाड़ा के संदर्भ में महिला श्रम भागीदारी दर एक अलग तरह की है ।

और तो और, घर से बाहर काम करने वाली भीलवाड़ा के संदर्भ में महिलाओं की दर बद से बदतर हो गई है। भीलवाड़ाके संदर्भ में एक चौथाई से अधिक महिलाएँ श्रम शक्ति में हैं, जबकि 2005 में यह एक तिहाई से अधिक थी।[12]

प्रतिक्रिया दें संदर्भ

1. "Rajya Sabha passes Women's Reservation Bill". द हिन्दू. मूल से 25 दिसंबर 2018 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 25 अगस्त 2010.
2. ↑ [hindu.com/2010/03/10/stories/2010031050880100.htm "Rajya Sabha passes Women's Reservation Bill"] जाँचें |url= मान (मदद). द हिन्दू. अभिगमन तिथि 25 अगस्त 2010.
3. ↑ Jayapalan (2001). Indian society and social institutions. Atlantic Publishers & Distri. पृ॰ 145. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 9788171569250. मूल से 27 सितंबर 2013 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 26 नवंबर 2010.
4. ↑ "Women in History". National Resource Center for Women. मूल से 19 जून 2009 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 24 दिसंबर 2006.
5. ↑ आदर्श पत्नी: त्रियम्बकयाज्वन द्वारा स्त्रीधर्मपद्धति (महिलाओं के कर्त्तव्यों में सहायक) (अनुवादक जूलिया लेसली), पेंग्विन 1995 आईएसबीएन 0-14-043598-0.
6. ↑ see extensive excerpts from strIdharmapaddhati at http://www.cse.iitk.ac.in/~amit/books/tryambakayajvan-1989-perfect-wife-stridharmapaddhati.html
7. ↑ Mishra, R. C. (2006). Towards Gender Equality. Authorspress. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 81-7273-306-2. मूल से 29 अक्तूबर 2010 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 26 नवंबर 2010.
8. ↑ Pruthi, Raj Kumar; Rameshwari Devi and Romila Pruthi (2001). Status and Position of Women: In Ancient, Medieval and Modern India. Vedam books. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 81-7594-078-6. मूल से 14 फ़रवरी 2012 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 26 नवंबर 2010.
9. ↑ कात्यायन द्वारा वर्त्तिका, 125, 2477
10. ↑ पतंजलि द्वारा अष्टध्यायी के लिए टिप्पणियां 3.3.21 और 4.1.14
11. ↑ आर.सी. मजूमदार और ए.डी. पुसल्कर (संपादक): भारतीय लोगों का इतिहास और संस्कृति. वॉल्यूम I, वैदिक युग. मुंबई: भारतीय विद्या भवन 1951, पी.394
12. ↑ "Vedic Women: Loving, Learned, Lucky!". मूल से 20 नवंबर 2006 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 24 दिसंबर 2006.

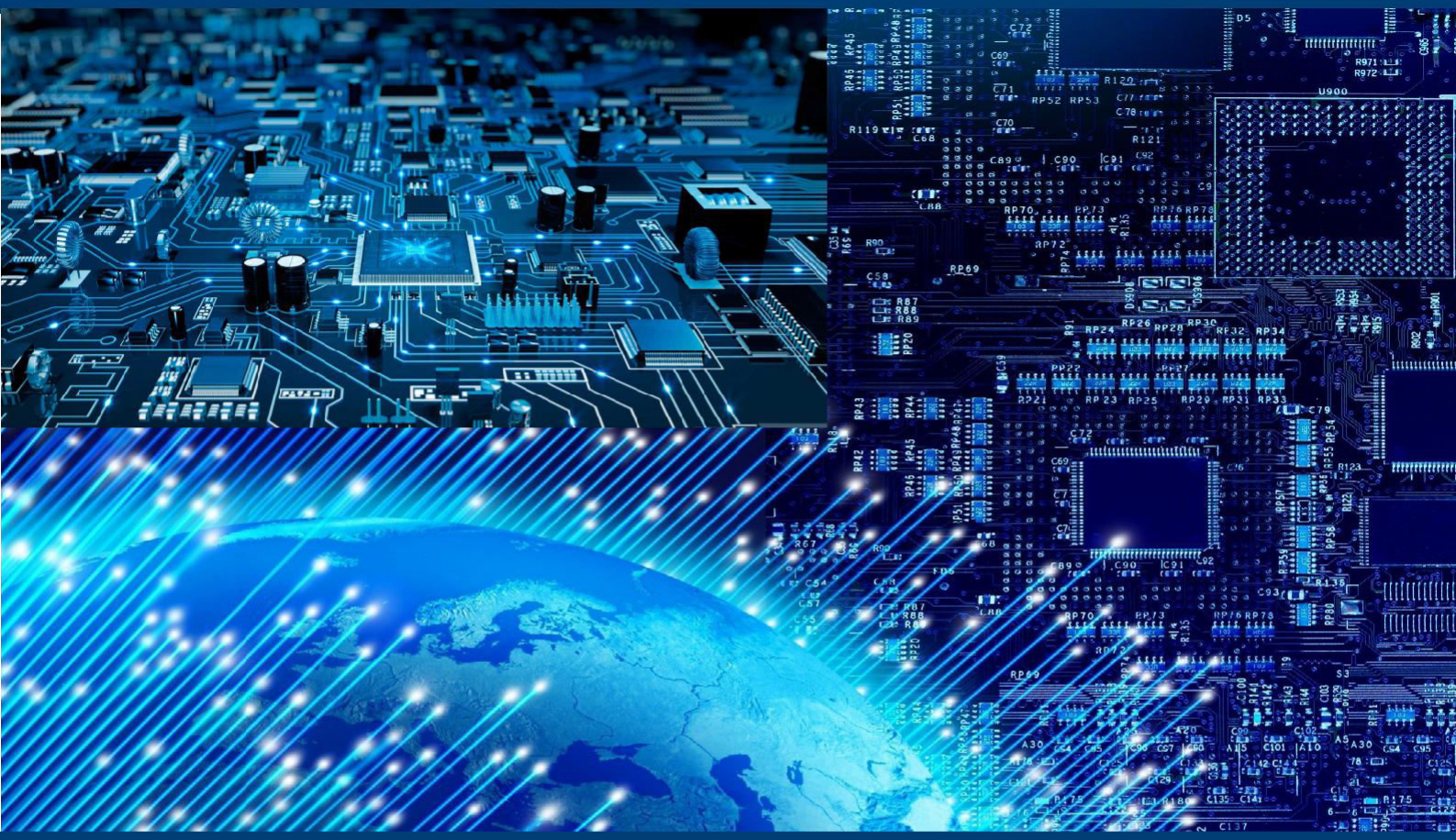

International Journal of Advanced Research in Arts, Science, Engineering & Management (IJARASEM)

| Mobile No: +91-9940572462 | Whatsapp: +91-9940572462 | ijarasem@gmail.com |